Minority Scholarship Online Application Trainers' Training

Workshop on Rights and Privileges of Minority Educational Institutions

BHARATIYA JAIN SANGHATANA,
Level 3, Muttha Chambers II, Senapati Bapat Marg, Pune 411016
Phone: 020-6605 0220
Email: info@bjsindia.org Website: www.bjsindia.org
Facebook: www.facebook.com/BJSIndia

BJS
Bharatiya Jain Sanghatana

MINORITY KNOWLEDGE CENTER

Constitutional Rights and Privileges of Minority Educational Institutions

- One-day Workshops for Trustees
- Awareness Sessions
- Digital Helpline
- Publications

जैन शिक्षण संस्थान के अल्पसंख्यक अधिकार व लाभ

जैन समाज लगभग पिछली दो सदियों से देशभर में 2500 से अधिक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से देश व देशवासियों की सेवा का भागीरथ कार्य कर रहा है.

भारत सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्ज़ा प्रदान किया है. भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है.पंजीकृत ट्रस्टों व सोसाईटियों द्वारा संचालित जैन समाज की शैक्षणिक संस्थाओं हेतु भारत सरकार द्वारा विविध अधिकारों व लाभों के प्रावधान किए गए हैं.

अल्पसंख्यक लाभों की जानकारी सभी जैन शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य हैं .विद्यालयों की संरचना के विकास की योजना (Infrastructural Development) के तहत् शिक्षण कक्ष (Class Rooms), छात्रावास (Hostel) भवन निर्माण, प्रयोगशाला (Laboratory) या पुस्तकालय (Library) मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री, अनुसंधान कार्य, प्रशिक्षण संस्थान (Coaching Institute) आदि के लिए भारत सरकार द्वारा सभी अनुदानित या बिन-अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के प्रावधान हैं.

इसी तरह शिक्षण संस्थाओं के संचालन हेतु भी नियम व कायदों मे अनेकों छूट का प्रावधान है. रोस्टर या बेकलोग, मुख्य अध्यापक या शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, शिक्षा अधिकार के तहत् आर्थिक दृष्टि से विपन्न विद्यार्थियों को 25% प्रवेश देने आदि नियमों में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं हेतु अनेक रियायतों का प्रावधान है.

जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से जैन शिक्षण संस्थाओं को प्राप्त अधिकार व लाभ के विषय पर भारतीय जैन संघटना विस्तृत अध्ययन एवं अनुसंधान करता है, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी से अवगत होना सभी जैन शिक्षण संस्थानो के संचालकों के लिए अनिवार्य है.

सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष है कि भारतीय जैन संघटना द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शीघ्र किया जायेगा, जिसमें भारतीय जैन संघटना के अल्पसंख्यक मामलों के विशेषज्ञ जैन शिक्षण संस्थाओं को विविध अधिकारों व लाभों की विस्तृत जानकारी देगें. साथ-साथ जैन शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रियाओं व तरीकों पर भी प्रकाश डालेंगे. सामाजिक व शैक्षणिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत जैन समाज की वर्तमान शिक्षण संस्थाओं के समुचित विकास के रचनात्मक प्रयासों हेतु भारतीय जैन संघटना संकल्पित है.

विनम्र निवेदन है कि इस अतिविशिष्ट कार्यशाला में ट्रस्टीगण स्वयं व उनकी शिक्षण संस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों एवं प्रधानाचार्य सहित उपस्थित रहने की कृपा करें.

Constitutional Rights of Minority Educational Institutions

Objectives

- To make sure that the minority constitutional rights and privileges should reach to the Jain Educational Institutes
- To encourage the current and prospective Jain managements to establish good quality educational institutes

Article 30 of Constitution:

- All Minorities, whether based on religion or language, shall have the **right to establish and administer educational institutions of their choice.**

Financial Schemes for Minority Institutes

1. Schemes for Construction, Equipment & Furniture

1.1 Grant-in-aid scheme by Maulana Azad Education Foundation

1.2 Scheme for Infrastructure Development in Minority Institutes (IDMI) by MHRD

2. Research and Studies

2.1 Scheme for Research and Studies

2.2 Scheme for Workshops/Seminars/ Conferences

Administrative Rights And Privileges

- Appointment
- Roster
- Promotion
- Termination
- Admission
- Fees formulation
- Rights to education (RTE)
- Rights to information (RTI)

Procedures to get minority status

- Certification as Minority Trust/Society
- To Apply to State Minority Dept.
- To Go in Appeal with National Commission for Minority Educational Institutes (NCMEI)

Important Legal Cases and Orders

- T.M.A. Pai Foundation Vs. State of Karnataka (2002) 8 Supreme Court Cases.
- Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka (2003) 6 Supreme Court Cases 697.
- P. A. Inamdar Vs. Sate of Maharashtra (2005) Supreme Court Cases 537.
- Christian Medical College, Vellor Vs. Union of India (2014) 2 Supreme Court Cases 305.
- Society for Unaided Private Schools of Rajsthan Vs. Union of India (2012) 6 Supreme Court Cases 102.
- Pramati Educational & Cultural Trust Vs. Union of India Writ Petition © No.416 of 2012 Judgment Dated 6th May 2014.